इंटर्नशिप से मिलेंगे कुशल कर्मी

बिज़नेस स्टैंडर्ड 'बीस्मार्ट एचआर कॉन्क्लेवः शेपिंग टुमॉरोज वर्कफोर्स' में बोले विशेषज्ञ

सोहिनी दास, जैडन मैथ्यू पॉल और अंजलि सिंह

मानव संसाधन (एचआर) विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार की नई इंटर्नशिप योजना के बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे जिसके तहत पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को हुनर-कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा आयोजित 'बीस्मार्ट एचआर कॉन्क्लेवः शेपिंग टुमॉरोज वर्कफोर्स' में उद्योग और अकादमिक जगह के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस नई इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर होगी कि इस पर किस तरीके अमल किया जाता है।

इस पैनल चर्चा में एचआर क्षेत्र के कई दिग्गज नामों ने हिस्सा लिया जिनमें पीपल ऐंड ऑर्गनाइजेशन के वरिष्ठ निदेशक और नोवो नॉरडिस्क इंडिया के बोर्ड सदस्य अमित कुमार दास, ओरेकल इंडिया में मानव पूंजी प्रबंधन और क्लाउड सॉल्यूशंस इंजीनियरिंग टीम के प्रमुख सूर्यनारायण अय्यर, स्टरलाइट पावर की समूह प्रमुख (एचआर ऑफिसर) रूही पांडेय, नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में एमबीए-एचआर की फैकल्टी प्रमुख हेमा बजाज का नाम शामिल है।

दास ने इसे सरकार का नेक इरादा बताते हुए कहा कि भारत में जनादेश हमेशा बेहतरी के लिए होता है। उन्होंने कहा कि इस योजना का जोर प्रतिभा विकास के निर्माण मॉडल पर आधारित है न कि प्रतिभा विकास के 'आयातित मॉडल' पर।

सीतारमण ने घोषणा की थी कि ताजा केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार, शीर्ष 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप के मौके की पेशकश करने वाली योजना के मौके के लिए पहल करेगी। कॉरपोरेट जगत से जुड़े मामलों का मंत्रालय इन कंपनियों के साथ सहयोग कर औद्योगिक कुशलता प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य संसाधनों को जुटाने की दिशा में काम करेगा।

इस योजना के तहत इंटर्न को 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा और साथ ही एक बार के लिए एकमुश्त 6000 रुपये की सहयोग राशि मिलेगी। इन प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण लागत का वहन कंपनियां अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

डॉ. हेमा बजाज, रूही पांडेय, अमित दास तथा डॉ. सूर्यनारायण जी अय्यर (बाएं से)

(सीएसआर) गतिविधियों के जरिये करेंगी। कंपनियां स्वैच्छिक आधार पर इस योजना का हिस्सा बनेंगी। साथ ही कंपनियां इंटर्न को स्थायी पद की पेशकश करने के लिए बाध्य नहीं होंगी।

पैनल विशेषज्ञों का कहना था कि व्यापक स्तर पर इस योजना का विचार बेहद अच्छा है लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, इसकी प्रगति की निगरानी करने के लिए एक प्रणाली तैयार करने की है। पांडेय ने कहा, 'सरकार को इस बात की निगरानी अवश्य करनी चाहिए कि छात्रों का प्रदर्शन कैसा रहा है और कंपनियों को भी छात्रों के लिए सार्थक परियोजनाएं तैयार करने की जरूरत है ताकि वे कौशल सीख सकें और जिस पर वे भविष्य में अमल करें।' विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस योजना के सार्थक प्रभाव के लिए योजना की अवधि कम से कम 6-8 हफ्ते तक होनी चाहिए। बजाज ने इस विचार को लागू करने और क्षेत्र आधारित सीख की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि कौशल निर्माण के संदर्भ के लिहाज से इंटर्नशिप बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कौशल और ज्ञान का तालमेल होना चाहिए।

उन्होंने बताया, 'जब छात्र इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तब हमें अपने पाठ्यक्रम के डिजाइन के जरिये यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब वे इंटर्नशिप करने के लिए आएं तो उनके पास कुछ कौशल पहले से ही मौजूद हो ताकि जब वे इंटर्नशिप के लिए आएं तब अपने समय का अधिकतम उपयोग करें।'

भारत में फिलहाल कुशल लोगों की बड़ी कमी है और रोजगार की दिशा में यह एक बड़ी समस्या भी है। दास ने कहा, 'भारत में 56 फीसदी कौशल की कमी है। यह बड़ी दिलचस्प विडंबना है कि बेरोजगारी दर 6-7 फीसदी के स्तर पर है और इसी अवधि के दौरान इसमें 20 फीसदी बेरोजगार लोग हैं।' दिलचस्प बात यह है कि जो लोग निरक्षर हैं, उनमें बेरोजगारी दर महज 0.5 फीसदी है वहीं जिन लोगों ने चौथी कक्षा तक पढ़ाई की है उनमें बेरोजगारी की दर 1.46 प्रतिशत है लेकिन स्नातकों के बीच बेरोजगारी की दर 18-20 फीसदी तक है।

विशेषज्ञों की इस दिशा में दो तरह की राय है। एक तरफ कुछ हजार नौकरियों के लिए लाखों लोग आवेदन दे रहे हैं (न केवल दफ्तरी कामकाज वाली नौकरियों के लिए बल्कि कामगार स्तर के काम के लिए भी।) वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में लोगों की कमी है। बजाज कहती हैं कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि तकनीकी विकास होने के साथ ही इन रोजगारों में भी बदलाव आए हैं और इनके लिए जिस तरह के कौशल की आवश्यकता है वह बेहद अलग है। उन्होंने कहा, 'ऑटोमेशन, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और डिजिटलीकरण किसी विशेष क्षेत्र या डोमेन तक ही सीमित नहीं हैं। कुछ रोजगार के मौके में बदलाव आया है लेकिन कौशल में कोई बदलाव नहीं आया है। शिक्षा और ज्ञानवर्धन के लिहाज से काफी कुछ किए जाने की गुंजाइश है।'

पांडे ने इसके लिए अपने क्षेत्र की मिसाल देते हुए कहा कि उनके अक्षय ऊर्जा परिचालन को लेकर किसी भी संस्थान में एक भी ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है जिसकी पेशकश कर वे भर्ती कर सकें।

भारत में करीब 4 करोड़ लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिनमें 2.24 करोड़ लोग सरकारी क्षेत्र में हैं जबकि बाकी निजी क्षेत्र से जुड़े हैं। पैनल में शामिल विशेषज्ञों का कहना था कि भारत में 2040 तक का समय है जब यहां की आबादी का बेहतर लाभ उठाया जा सकेगा। दास का कहना था, 'हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां प्रौद्योगिकी को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मशीन भी सीख रहे हैं और बेहतर बन रहे हैं।'

एचआर विशेषज्ञों ने एचआर की प्रक्रिया में एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पांडे कहती हैं, 'एआई ने हमारी जिंदगी आसान कर दी है और युवा पीढ़ी इसके साथ बेहद सहज है। एचआर के तौर पर हम एआई के इस्तेमाल के साथ इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि इस तरह से समूह की पहचान की जा सकती है जो कम दिलचस्पी लेने वाले हों और यह भी देखा जा सकता है और क्या किया जा सकता है।'

एचआर से जुड़े कार्यों में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न पीढ़ियों वाली विविधतापूर्ण टीमें तैयार करने पर काम किया जा सकता है।

बजाज ने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में दोबारा नवाचार देखा जा रहा है और एक सबसे बड़ा बदलाव यह है कि न केवल विचार को समझा जा रहा है बल्कि इसे जीवन की वास्तविक समस्याओं, चुनौतियों और अवसरों पर लागू करके देखा जा रहा है।'

बजाज का कहना है कि उनकी टीम एआई नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, 'हमारे छात्र एआई का इस्तेमाल जरूर करेंगे और वे चैटजीपीटी का इस्तेमाल भी करेंगे। यह अच्छी बात भी है। इसीलिए हम एक नीति तैयार कर रहे हैं कि छात्र क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं।'

जन धन योजना के 10 साल पूरे

'वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' के 10 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को कहा कि यह योजना सम्मान, सशक्तीकरण और राष्ट्र के आर्थिक जीवन में भागीदारी के अवसर का प्रतीक है। मोदी ने जन धन योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वालों की भी सराहना की और कहा कि यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने आधिकारिक खाते पर लिखा, 'आज एक ऐतिहासिक दिन है, जन धन योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं और इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन-रात एक करने वाले सभी

लोगों को भी बहुत-बहुत बधाई।'

उन्होंने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों खासकर महिलाओं, युवाओं तथा वंचित समुदायों को सम्मान देने में सबसे आगे रही है। प्रधानमंत्री ने पेशेवर मंच 'लिंक्डइन' पर बाद में लिखा आज प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू हुए एक दशक हो गया है और यह पहल महज एक नीति नहीं है। यह एक ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास है, जहां हर नागरिक, चाहे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उसकी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच हो।

मोदी ने कहा, 'आप में से कई लोग, खासकर युवा सोच रहे होंगे, यह इतना महत्त्वपूर्ण क्यों है? आखिरकार, इस युग में बैंक खाता होना बेहद ही बुनियादी बात है और इसे सामान्य बात भी माना जाता है। हालांकि, जब हमने 2014 में सत्ता संभाली, तो स्थिति बहुत अलग थी। आजादी के करीब 65 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे लगभग आधे परिवारों के लिए बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच दूर का सपना थी।' **भाषा**

2029 तक 3 गुना बढ़ेगा डिजिटल लेनदेन

राघव अग्रवाल

भारत में साल 2028-29 तक डिजिटल वित्तीय लेनदेन की संख्या 481 अरब हो जाएगी, जो साल 2023-24 में 159 अरब थी। पीडब्ल्यूसी इंडिया की एक रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। कंसल्टेंसी फर्म ने बुधवार को अपनी 'द इंडियन पेमेंट्स हैंडबुक 2024-29' में कहा है कि इस दौरान डिजिटल भुगतान का मूल्य 265 लाख करोड़ रुपये से दोगुना होकर 593 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से लेनदेन की मात्रा 57 फीसदी तक बढ़ जाएगी। वित्त वर्ष 2029 तक यूपीआई लेनदेन की संख्या मौजूदा 131 अरब से बढ़कर 439 अरब हो जाएगी। भारत में कुल खुदरा डिजिटल भुगतान में यूपीआई की 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी है और इसके साल 2028-29 तक बढ़कर 91 फीसदी होने की उम्मीद है। यूपीआई के पांव पसारने के बीच क्रेडिट कार्ड की पकड़ भी बरकरार रहेगी। साल 2023-24 में इस उद्योग ने 1.6 करोड़ से अधिक नए क्रेडिट कार्ड जारी किए थे, जिससे कुल क्रेडिट कार्ड की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा पार

कर गई। रिपोर्ट में कहा गया है, 'नए कार्ड के जारी होने के साथ उद्योग में लेनदेन की मात्रा में 22 फीसदी और मूल्य में 28 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया।' साथ ही कहा गया है कि साल 2028-29 तक क्रेडिट कार्ड से होने वाले लेनदेन की संख्या भी 20 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, कार्डधारकों की बदलती प्राथमिकताओं से डेबिट कार्ड से होने वाले लेनदेन की मात्रा और मूल्य दोनों में गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2022 में डेबिट कार्ड से लेनदेन की मात्रा 3.94 अरब थी, जो वित्त वर्ष 2024 में घट कर 2.29 अरब रह गई।

ई–नीलामी के 9वें दौर के लिए सार्वजनिक सूचना पुंज लॉयड लिमिटेड (परिसमापन में)

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अनुसार कंपनी की चालू व्यवसाय के आधार पर और वैकल्पिक रूप से कंपनी की विभिन्न आस्तियों की बिक्री

सार्वजनिक ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार, पुंज लॉयड लिमिटेड–परिसमापन में (''कंपनी'') की विभिन्न 'परिसंपत्तियों के सेट' की बिक्री के लिए ई–नीलामी के 8वें दौर की घोषणा की जाती है, जिसमें कंपनी की बिक्री एक चालू व्यवसाय के आधार पर और सामूहिक आधार पर कंपनी की कुछ परिसंपत्तियों की बिक्री शामिल है। कंपनी माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के 27 मई 2022 के आदेश के अनुसार परिसमापन की प्रक्रिया के अंतर्गत है। कंपनी की स्थापना 1988 में हुई थी, यह एक विविधतापूर्ण व्यवसाय समूह है, जो इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (''ईपीसी'') के व्यवसाय में लगा हुआ है, जिसकी भौगोलिक उपस्थिति भारत और मध्य पूर्व के देशों में है, तथा यह रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण क्षमताओं के साथ–साथ ऊर्जा–सड़क और बुनियादी ढांचे में सेवाएं प्रदान करता है।

इच्छुक आवेदक कंपनी की वेबसाइट **http://www.punjlloydgroup.com/liquidation-documents** और ई–नीलामी वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net पर अपलोड किए गए विस्तृत 'ई–नीलामी के 9वें दौर के लिए संपत्ति बिक्री प्रक्रिया ज्ञापन' (''एएसपीएम'') का संदर्भ ले सकते हैं।

नीलामी बिक्री ई–नीलामी प्लेटफॉर्मः **https://ncltauction.auctiontiger.net** के माध्यम से की जाएगी।

ई–नीलामी के 9वें दौर में बेची जाने वाली कंपनी की संपत्तियों का विवरण इस प्रकार हैः

सम्पत्ति का सेट	सम्पत्ति का विवरण	बिक्री का तरीका	ई–नीलामी की तिथि और समय	आरक्षित मूल्य (रु. में)	ईएमडी राशि (रु. में) और जमा करने की अंतिम तिथि
श्रेणी ए*					
सम्पत्ति सेट 1	पुंज लॉयड लिमिटेड की समग्र बिक्री ('एएसपीएम' में दिए गए कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर)	चल रही व्यवसाय के आधार पर	26 सितम्बर 2024 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	449.00 करोड़	10.00 करोड़ 23 सितम्बर 2024 को या उससे पहले
सम्पत्ति सेट 2	पुंज लॉयड लिमिटेड की समग्र बिक्री (एसेट सेट 1 के अनुसार परिसंपत्तियों को छोड़कर और लाइव आर्बिट्रेशन मामलों के लिए कोई अग्रिम मूल्य नहीं और ट्रांसफर तिथि के बाद लाइव आर्बिट्रेशन मामलों में शुद्ध प्राप्तियां, एससीसी और कंपनी के बीच 50:50 शेयरिंग अनुपात पर वितरित की जाएंगी। एसेट सेट 2 की अन्य शर्तें एएसपीएम में उल्लिखित हैं)	चल रही व्यवसाय के आधार पर	26 सितम्बर 2024 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	352.00 करोड़	10.00 करोड़ 23 सितम्बर 2024 को या उससे पहले
श्रेणी सी*					
सम्पत्ति सेट 3	पुंज लॉयड लिमिटेड की आर्बिट्रेशन परिसंपत्तियों की बिक्री	सामूहिक आधार पर	27 सितम्बर 2024 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	225 करोड़	10.00 करोड़ 24 सितम्बर 2024 को या उससे पहले
श्रेणी डी*					
सम्पत्ति सेट 4	मालनपुर, मध्य प्रदेश में लीजहोल्ड भूमि, भवन और प्लांट एवं मशीनरी की बिक्री	सामूहिक आधार पर	27 सितम्बर 2024 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	96.13 करोड़	9.61 करोड़ 24 सितम्बर 2024 को या उससे पहले
सम्पत्ति सेट 5	काकरापारा साइट, गुजरात पर प्लांट और मशीनरी की बिक्री	सामूहिक आधार पर	27 सितम्बर 2024 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	62 लाख	6.20 लाख 24 सितम्बर 2024 को या उससे पहले
सम्पत्ति सेट 6	बांग्लादेश भूटान रोड प्रोजेक्ट साइट पर प्लांट एवं मशीनरी की बिक्री	सामूहिक आधार पर	27 सितम्बर 2024 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	1.22 करोड़	12.20 लाख 24 सितम्बर 2024 को या उससे पहले

*यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि श्रेणी ए के अंतर्गत परिसंपत्ति सेट 1 या परिसंपत्ति सेट 2 के लिए सफल बोलीदाता घोषित किया जाता है, अर्थात कंपनी की बिक्री चालू व्यवसाय के आधार पर की जाती है, तो परिसमापक के पास क्रमशः श्रेणी सी और श्रेणी डी के अंतर्गत सभी परिसंपत्ति सेटों की ई–नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अलावा, परिसमापक के पास ई–नीलामी के 9वें दौर के अंतर्गत बेची जा रही किसी भी या सभी श्रेणियों औरध्या परिसंपत्तियों के सेट की ई–नीलामी रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

इसके अलावा, संशोधित आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित श्रेणियों और/या परिसंपत्तियों के सेट के लिए सभी इच्छुक बोलीदाताओं को 13 सितम्बर 2024 को या उससे पहले 'एएसपीएम' में दिए गए अपेक्षित पात्रता दस्तावेजों के साथ अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करनी होगी।

परिसमापक ई–नीलामी के 9वें दौर में बेची जा रही किसी भी या सभी श्रेणियों और/या परिसंपत्तियों के सेट के लिए समयसीमा सहित बिक्री प्रक्रिया की मुख्य शर्तों को लागू कानूनों और विनियमों के तहत स्वीकार्य सीमा तक संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी या सभी श्रेणियों औरध्या परिसंपत्तियों के सेट के लिए बिक्री प्रक्रिया समयसीमा के संबंध में किसी भी समयसीमा के संशोधनधविस्तार के बारे में कोई भी जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और पात्र/योग्य/सफल बोलीदाता(ओं) को सूचित की जाएगी।

सम्पत्ति सेट 1 और 2 तथा संपत्ति सेट 4 के बारे में जानकारी और क्रेडेंशियल वाले छोटे वीडियो तक पहुंचने के लिए कृपया नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें :

(सम्पत्ति सेट 1 और 2) (सम्पत्ति सेट 4)

सम्पत्ति सेट 1 और 2 तथा संपत्ति सेट 4 के बारे में बिक्री टीजर के लिए कृपया नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें

(सम्पत्ति सेट 1 और 2) (सम्पत्ति सेट 4)

इसमें निहित कोई भी बात कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बाध्यकारी प्रस्ताव या प्रतिबद्धता नहीं होगी, जिसमें कंपनी की समग्र बिक्री भी शामिल है, जो कि चालू चिंता के आधार पर होगी।

यदि किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया श्री अश्विनी मेहरा से **LQ.PUNJ@in.gt.com** या **Mehra.ashwini@gmail.com** या श्री सुरेन्द्र राज गंग से **Surendra.raj@in.gt.com** (जीटी रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज एलएलपी, आईपीई के प्रतिनिधि जिन्हें परिसमापक के पेशेवर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है) पर संपर्क करें।

हस्ता/–
अश्विनी मेहरा
परिसमापक
(पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00388/2017-18/10706)
पुंज लॉयड लिमिटेड – परिसमापन में
असाइनमेंट के लिए प्राधिकरण –30 जून 2025 तक वैधता
पत्राचार पताः
श्री अश्विनी मेहरा, परिसमापक
पुंज लॉयड लिमिटेड
सी/ओ श्री सुरेंद्र राज गंग
जीटी रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज एलएलपी एल–41, कनॉट सर्कस नई दिल्ली – 110001, ईः LQ.Punj@in.gt.com
आईबीबीआई के साथ लिक्विडेटर का पंजीकृत पताः
सी 1201, सलारपुरिया मैग्निफिसिया, ओल्ड मद्रास रोड. बैंगलोर 560016
ईः **Mehra.Ashwini@gmail.com**

दिनांक : 29 अगस्त 2024
स्थान : नई दिल्ली